

महिला उद्यमिता विकास और स्वयं सहायता समूह :

अवसर, चुनौतियाँ और संभावनाएँ

डॉ शाहेदा सिद्दीकी

सह प्राध्यापक (समाजशास्त्र)

शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

एवं

दीपेन्द्र कुमार सतनामी

शोध छात्र

सारांश

महिलाओं की आर्थिक भागीदारी किसी भी समाज के समावेशी विकास का महत्वपूर्ण सूचक मानी जाती है। भारत में लंबे समय तक महिलाएँ घरेलू कार्यों तक सीमित रहीं, जिसके कारण उनकी आर्थिक निर्भरता और सामाजिक असमानता बनी रही। स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups–SHGs) ने इस स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। सामूहिक बचत, ऋण सुविधा, कौशल प्रशिक्षण और सामाजिक सहयोग के माध्यम से SHG महिलाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित करते हैं। प्रस्तुत लेख में महिला उद्यमिता विकास में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका, उनसे प्राप्त अवसर, सामने आने वाली चुनौतियाँ तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि SHG महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक प्रतिष्ठा और निर्णय-निर्माण क्षमता प्रदान करते हैं, किन्तु बाजार, तकनीकी ज्ञान और संस्थागत सहयोग की कमी उनके विकास को सीमित करती है।

प्रस्तावना

भारतीय समाज परंपरागत रूप से पितृसत्तात्मक रहा है, जहाँ आर्थिक संसाधनों और उत्पादन के साधनों पर पुरुषों का वर्चस्व रहा। महिलाओं की भूमिका घरेलू श्रम, परिवार देखभाल और अप्रत्यक्ष आर्थिक योगदान तक सीमित रही। शिक्षा, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के विस्तार के बावजूद महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर अपेक्षाकृत कम रही है।



ऐसी परिस्थिति में स्वयं सहायता समूहों की अवधारणा ने महिलाओं को संगठित कर आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम प्रदान किया। यह केवल वित्तीय कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। SHG महिलाओं में सामूहिक चेतना, सहयोग और आत्मविश्वास का विकास करते हैं, जो उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करता है।

आज ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में छोटे-छोटे व्यवसाय – जैसे डेयरी, ब्यूटीपार्लर, सिलाई-कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण, मसाला निर्माण, रेडीमेड वस्त्र, किराना दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग – SHG आधारित महिला उद्यमिता के उदाहरण बन चुके हैं।

महिला उद्यमिता की अवधारणा

महिला उद्यमिता से आशय महिलाओं द्वारा किसी आर्थिक गतिविधि, व्यवसाय या उद्योग की स्थापना, संचालन एवं प्रबंधन से है। यह केवल आय अर्जित करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब कोई महिला जोखिम उठाकर संसाधनों का संयोजन करती है, उत्पादन या सेवा प्रदान करती है तथा बाजार से जुड़ती है, तब वह उद्यमी की भूमिका निभाती है।

पारंपरिक भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका मुख्यतः घरेलू कार्यों तक सीमित रही है। वे परिवार की आर्थिक गतिविधियों में अप्रत्यक्ष योगदान तो देती थीं, किन्तु उन्हें स्वामित्व और निर्णय लेने का अधिकार कम प्राप्त था। शिक्षा, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और सरकारी योजनाओं के प्रसार ने महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश करने के अवसर प्रदान किए। परिणामस्वरूप महिलाएँ अब छोटे उद्योग, स्वरोजगार, सेवा क्षेत्र तथा गृह आधारित उद्योगों में सक्रिय भागीदारी करने लगी हैं।

महिला उद्यमिता के प्रमुख तत्वों में पहल करने की क्षमता, जोखिम वहन, संसाधनों का प्रबंधन, नवाचार, नेतृत्व तथा निर्णय-निर्माण शामिल हैं। यह केवल व्यक्तिगत प्रगति तक सीमित नहीं रहती बल्कि परिवार और समाज के विकास को भी प्रभावित करती है। एक महिला उद्यमी अपने परिवार की आय बढ़ाती है, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करती है तथा अन्य महिलाओं को प्रेरित करती है।



समाजशास्त्रीय दृष्टि से महिला उद्यमिता सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है। यह महिलाओं की सामाजिक स्थिति को मजबूत करती है, लैंगिक असमानता को कम करती है तथा आत्मसम्मान को बढ़ाती है। विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म वित्त की उपलब्धता ने ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को गति प्रदान की है। अतः महिला उद्यमिता आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया है, जो महिलाओं को आश्रित से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर करती है।

स्वयं सहायता समूह : अवधारणा और कार्यप्रणाली

स्वयं सहायता समूह (Self Help Group–SHG) समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 10 से 20 व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं, का एक छोटा स्वैच्छिक संगठन होता है, जिसका उद्देश्य सामूहिक बचत, पारस्परिक सहयोग और लघु ऋण के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण प्राप्त करना है। इसकी मूल भावना “अपनी सहायता स्वयं” पर आधारित होती है। समूह के सदस्य नियमित रूप से साप्ताहिक या मासिक बचत जमा करते हैं और उसी संचित धनराशि को आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को ऋण के रूप में प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया से साहूकारों पर निर्भरता कम होती है तथा वित्तीय अनुशासन विकसित होता है। कुछ समय बाद समूह बैंक से जुड़कर औपचारिक ऋण प्राप्त करता है और सदस्यों को स्वरोजगार या लघु उद्यम स्थापित करने में सहायता करता है। समूह की नियमित बैठकों में आय-व्यय, ऋण वापसी और भविष्य की योजनाओं पर सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह केवल आर्थिक गतिविधि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सदस्यों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सहभागिता भी बढ़ाता है, जो उन्हें आत्मनिर्भर जीवन की ओर अग्रसर करता है।

महिला उद्यमिता विकास में स्वयं सहायता समूह (SHG) की भूमिका

महिला उद्यमिता विकास के संदर्भ में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group–SHG) एक प्रभावी सामाजिक-आर्थिक तंत्र के रूप में उभरे हैं। पारंपरिक भारतीय समाज में महिलाओं की आर्थिक भूमिका सीमित और परोक्ष रही है, जिसके कारण उनमें पूंजी, प्रशिक्षण, बाजार और निर्णय-निर्माण



की क्षमता का अभाव पाया जाता था। SHG मॉडल ने इन बाधाओं को सामूहिक शक्ति और सहयोग की भावना के माध्यम से कम किया है तथा महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में प्रेरित किया है।

सबसे पहले, SHG महिलाओं को वित्तीय सशक्तिकरण प्रदान करते हैं। समूह के सदस्य नियमित बचत करते हैं और उसी राशि से आंतरिक ऋण प्राप्त करते हैं। इससे महिलाओं की साहूकारों पर निर्भरता कम होती है तथा वे छोटे व्यवसाय आरंभ करने का साहस कर पाती हैं। बैंक से जुड़ने के बाद समूह को कम ब्याज पर ऋण मिलता है, जिससे महिलाएँ सिलाई-कढ़ाई, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, किराना दुकान, ब्यूटीपार्लर आदि उद्यम शुरू करती हैं। इस प्रकार SHG महिला उद्यमिता के लिए प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम बनता है।

दूसरे, SHG कौशल विकास और प्रशिक्षण का मंच प्रदान करते हैं। विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएँ समूहों के माध्यम से महिलाओं को उत्पादन, पैकेजिंग, विपणन और लेखांकन का प्रशिक्षण देती हैं। इससे महिलाएँ केवल श्रमिक नहीं रहती बल्कि उद्यमी के रूप में कार्य करना सीखती हैं। प्रशिक्षण से उनमें नवाचार की क्षमता बढ़ती है और वे स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर आय के नए स्रोत विकसित करती हैं।

तीसरे, SHG महिलाओं में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं। नियमित बैठकों, चर्चा और सामूहिक निर्णय-निर्माण से महिलाएँ सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने लगती हैं। आर्थिक योगदान बढ़ने से परिवार में उनकी भूमिका मजबूत होती है और वे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा निवेश से जुड़े निर्णयों में भागीदारी करने लगती हैं। यह परिवर्तन महिला उद्यमिता की सामाजिक स्वीकृति को बढ़ाता है।

चौथे, SHG सामूहिक उद्यम स्थापना को प्रोत्साहित करते हैं। कई महिलाएँ मिलकर उत्पादन इकाइयाँ चलाती हैं, जिससे जोखिम कम होता है और लाभ स्थिर रहता है। सामूहिक विपणन से उत्पादों की बिक्री बढ़ती है तथा बाजार तक पहुँच आसान होती है। इससे महिला उद्यमिता टिकाऊ और दीर्घकालिक बनती है।

अंततः, SHG सामाजिक परिवर्तन का माध्यम भी है। यह महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाता है और लैंगिक असमानता को कम करता है। महिलाएँ



पंचायत और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने लगती हैं, जिससे उनकी नेतृत्व भूमिका विकसित होती है।

इस प्रकार स्वयं सहायता समूह महिला उद्यमिता विकास की आधारशिला हैं। वे वित्तीय संसाधन, कौशल, आत्मविश्वास और सामाजिक समर्थन प्रदान कर महिलाओं को आश्रित से आत्मनिर्भर तथा श्रमिक से उद्यमी बनने की दिशा में अग्रसर करते हैं।

महिला उद्यमिता की प्रमुख चुनौतियाँ

महिला उद्यमिता के विकास के बावजूद इसके समक्ष अनेक सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक बाधाएँ विद्यमान हैं। सबसे बड़ी चुनौती पूंजी की कमी है। अधिकांश महिलाओं के पास संपत्ति या जमानत नहीं होती, जिसके कारण उन्हें पर्याप्त ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है और वे छोटे स्तर तक ही सीमित रह जाती हैं।

दूसरी प्रमुख समस्या बाजार तक सीमित पहुँच है। महिलाएँ उत्पाद तो तैयार कर लेती हैं, परंतु उचित विपणन, ब्रांडिंग और ग्राहक नेटवर्क के अभाव में उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। डिजिटल और तकनीकी ज्ञान की कमी भी उनके व्यवसाय के विस्तार में बाधक बनती है।

सामाजिक स्तर पर पारिवारिक जिम्मेदारियाँ और पारंपरिक धारणाएँ महिलाओं के कार्य समय और गतिशीलता को सीमित करती हैं। कई बार परिवार और समाज की स्वीकृति न मिलने से महिलाएँ जोखिम उठाने से हिचकिचाती हैं।

प्रशिक्षण और प्रबंधन कौशल का अभाव भी महत्वपूर्ण चुनौती है। लेखांकन, पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण तथा प्रतिस्पर्धी बाजार की समझ न होने से व्यवसाय टिकाऊ नहीं रह पाता।

इस प्रकार वित्तीय, सामाजिक और तकनीकी बाधाएँ महिला उद्यमिता के विकास की गति को धीमा करती हैं, जिन्हें दूर किए बिना व्यापक आर्थिक सशक्तिकरण संभव नहीं है।

महिला उद्यमिता की भविष्य की संभावनाएँ

वर्तमान परिवर्तित सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में महिला उद्यमिता की संभावनाएँ अत्यंत व्यापक हैं। डिजिटल तकनीक और इंटरनेट के विस्तार ने व्यवसाय के पारंपरिक स्वरूप को बदल दिया है, जिससे महिलाएँ घर से ही ऑनलाइन विपणन, ई-कॉमर्स और सेवा आधारित कार्यों से जुड़ सकती



हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल भुगतान और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से बाजार तक उनकी पहुँच पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गई है। सरकारी योजनाएँ, कौशल विकास कार्यक्रम और स्वयं सहायता समूह आधारित वित्तीय सहायता महिलाओं को प्रशिक्षण, पूंजी और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय संसाधनों पर आधारित सूक्ष्म उद्योग, जैविक उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र में महिलाओं के लिए नए रोजगार अवसर विकसित हो रहे हैं। आने वाले समय में हरित उद्यम (Green Entrepreneurship), घरेलू उद्योग और सामुदायिक उत्पादन इकाइयाँ महिला उद्यमिता के प्रमुख क्षेत्र बन सकते हैं। यदि तकनीकी प्रशिक्षण, विपणन सहयोग और संस्थागत समर्थन को और मजबूत किया जाए तो महिलाएँ केवल लघु उद्यम तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि मध्यम एवं नवाचार आधारित उद्योगों में भी भागीदारी कर सकेंगी। इस प्रकार महिला उद्यमिता भविष्य में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और समावेशी विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला सिद्ध हो सकती है।

सुझाव

महिला उद्यमिता को प्रभावी और टिकाऊ बनाने के लिए बहुआयामी प्रयास आवश्यक हैं। सबसे पहले महिलाओं को नियमित एवं व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें उत्पादन के साथ-साथ विपणन, पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और डिजिटल भुगतान का ज्ञान भी शामिल हो। इससे उनका व्यवसाय प्रतिस्पर्धी बन सकेगा।

दूसरे, बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को महिला उद्यमियों के लिए ऋण प्रक्रिया सरल और लचीली बनानी चाहिए तथा बिना जमानत या कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। स्वयं सहायता समूहों को भी बड़े स्तर के ऋण और कार्यशील पूंजी की सुविधा दी जानी चाहिए ताकि वे लघु से मध्यम उद्यमों की ओर बढ़ सकें।

तीसरे, स्थानीय स्तर पर “महिला विपणन केंद्र” या बिक्री मंच स्थापित किए जाएँ, जहाँ महिलाएँ अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकें। साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए डिजिटल प्रशिक्षण आवश्यक है।

चौथे, परिवार और समाज में जागरूकता कार्यक्रम चलाकर महिलाओं की कार्यभागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए तथा बाल देखभाल जैसी सहायक सुविधाएँ विकसित की जाएँ।



अंततः सरकारी विभाग, गैर-सरकारी संगठन और बैंक मिलकर परामर्श एवं मार्गदर्शन तंत्र विकसित करें, जिससे महिला उद्यमिता दीर्घकालिक रूप से सफल और आत्मनिर्भर बन सके।

निष्कर्ष

महिला उद्यमिता विकास सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों ने प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य किया है। SHG ने महिलाओं को सामूहिक बचत, ऋण सुविधा, प्रशिक्षण और सामाजिक सहयोग प्रदान कर उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की आय में वृद्धि हुई, आत्मविश्वास बढ़ा और परिवार तथा समाज में उनकी निर्णय-निर्माण क्षमता सुदृढ़ हुई। इस प्रकार महिला उद्यमिता केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि सशक्तिकरण और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का माध्यम भी बन गई है।

फिर भी पूंजी की कमी, विपणन समस्या, तकनीकी ज्ञान का अभाव और सामाजिक बाधाएँ इसके व्यापक विस्तार में अवरोध उत्पन्न करती हैं। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, डिजिटल साक्षरता और संस्थागत समर्थन को मजबूत करना आवश्यक है। यदि महिलाओं को उचित अवसर और सहयोग प्रदान किया जाए तो वे लघु उद्यमों से आगे बढ़कर नवाचार आधारित और टिकाऊ उद्योग स्थापित कर सकती हैं।

अतः स्पष्ट है कि स्वयं सहायता समूह आधारित महिला उद्यमितासमावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भर समाज निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधारशिला सिद्ध हो सकती है।

सन्दर्भ

1. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). Status of Microfinance in India (various years). Mumbai: NABARD.
2. Ministry of Rural Development, Government of India. DeendayalAntyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM): Framework and Implementation Guidelines. New Delhi.
3. Self Employed Women's Association (SEWA). Annual Reports and Case Studies on Women's Livelihoods. Ahmedabad: SEWA.
4. Mayoux, Linda. (2001). "Tackling the Down Side: Social Capital, Women's Empowerment and Micro-finance in Cameroon." Development and Change, 32(3).



5. Kabeer, Naila. (2005). "Is Microfinance a 'Magic Bullet' for Women's Empowerment? Analysis of Findings from South Asia." *Economic and Political Weekly*, 40(44-45).
6. Sharma, K. C. (2007). *Microfinance and Women Empowerment*. New Delhi: Deep & Deep Publications.
7. Swain, Ranjula Bali & Varghese, A. (2009). "Does Self Help Group Participation Lead to Asset Creation?" *World Development*, 37(10).
8. Harper, Malcolm. (2012). *Practical Microfinance: A Training Guide for South Asia*. New Delhi: Vistaar Publications.
9. APMAS. (2009). *Quality and Sustainability of Self-Help Groups in India*. Hyderabad: Andhra Pradesh MahilaAbhivruddhi Society.
10. Reserve Bank of India. (2008). *Report of the Committee on Financial Inclusion (Rangarajan Committee)*. Mumbai: RBI.
11. Government of India. (2015). *National Policy for Skill Development and Entrepreneurship*. New Delhi: Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.
12. Desai, Vasant. (2011). *Small Scale Industries and Entrepreneurship*. Mumbai: Himalaya Publishing House.

